



Lakshya IAS

academy

13

Sep 2026

DAILY CURRENT AFFAIRS



Mr. R.P. Singh Sir
(MD)



1. उपराष्ट्रपति ने दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव को “लघु भारत” बताया, विकास पहलों की सराहना की

सितंबर २०२६ में, भारत के उपराष्ट्रपति ने दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव को “लघु भारत” बताया, जिसमें इसकी समृद्ध सांस्कृतिक विविधता, सामंजस्यपूर्ण सह-अस्तित्व और समावेशी विकास मॉडल को रेखांकित किया गया। उन्होंने क्षेत्र की विकास पहलों की सराहना की और समुदायों, परंपराओं तथा संस्कृतियों के इसके अनूठे मिश्रण का उल्लेख किया। उपराष्ट्रपति ने बुनियादी ढांचे, पर्यटन और सामाजिक विकास में केंद्र शासित प्रदेश की प्रगति की सराहना की तथा विविधता में एकता और संतुलित विकास के उदाहरण के रूप में इसकी भूमिका पर जोर दिया।



Vice President Describes Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu as “Mini India”, Praises Development Initiatives

In September 2026, the Vice President of India described the Union Territory of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu as “Mini India”, highlighting its rich cultural diversity, harmonious coexistence and inclusive growth model. He praised the region's development initiatives and noted its unique blend of communities, traditions and cultures. The Vice President appreciated the Union Territory's progress in infrastructure, tourism and social development, emphasizing its role as an example of unity in diversity and balanced development.



मुख्य बिंदु:

- विविध संस्कृति एकता को मजबूत करती है: उपराष्ट्रपति ने केंद्र शासित प्रदेश को “लघु भारत” बताया, जिसमें इसकी विविध समुदायों, भाषाओं, परंपराओं और सामंजस्यपूर्ण सह-अस्तित्व को रेखांकित किया गया।
- विकास पहल क्षेत्र को बदल रही हैं: बुनियादी ढांचे, संपर्क, पर्यटन और सार्वजनिक सेवाओं में विकास प्रयास केंद्र शासित प्रदेश में जीवन स्तर में सुधार में योगदान दे रहे हैं।
- पर्यटन क्षमता पर जोर: प्रशासन की पहल का उद्देश्य क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन के अवसरों को बढ़ावा देना तथा स्थानीय रोजगार सृजित करना है।

Key Points:

- Diverse culture strengthens unity: The Vice President described the Union Territory as “Mini India”, highlighting its diverse communities, languages, traditions and harmonious coexistence.
- Development initiatives transform region: Development efforts in infrastructure, connectivity, tourism and public services are contributing to improved living standards across the Union Territory.
- Tourism potential receives emphasis: The administration's initiatives seek to promote the region's natural beauty, cultural heritage and tourism opportunities while generating local employment.

2. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने भारत के असंगठित गैर-कृषि क्षेत्र के लिए पहली बार जिला-स्तरीय अनुमान जारी किए

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने भारत के असंगठित गैर-कृषि क्षेत्र के लिए पहली बार जिला-स्तरीय अनुमान जारी किए हैं, जो जिलों में आर्थिक गतिविधियों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं। अनुमानों से महत्वपूर्ण भौगोलिक संकेन्द्रण का पता चलता है, जिसमें शीर्ष ५० जिले कुल क्षेत्रीय गतिविधि का लगभग ** प्रतिशत हिस्सा रखते हैं। आंकड़े उद्यमों, रोजगार और आर्थिक उत्पादन के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं, जिससे नीति-निर्माताओं को क्षेत्रीय विविधताओं को बेहतर ढंग से समझने में सहायता मिलती है। इससे साक्ष्य-आधारित नीति-निर्माण को मजबूत करने और देश के बड़े असंगठित कारोबारी क्षेत्र के लिए अधिक लक्षित योजना बनाने में सहायता मिलने की उम्मीद है।



मुख्य बिंदु:

- जिला-स्तरीय आंकड़े नीति-निर्माण में सुधार करते हैं: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने पहली बार एएसयूएसई २०२५ के आंकड़ों का उपयोग करके भारत के असंगठित गैर-कृषि क्षेत्र के लिए जिला-स्तरीय अनुमान जारी किए हैं।
- शीर्ष जिले प्रमुख गतिविधि संचालित करते हैं: शीर्ष ५० जिलों में इस क्षेत्र द्वारा उत्पन्न प्रतिष्ठानों, कार्यबल और सकल मूल्य वर्धित का लगभग एक-तिहाई हिस्सा है।
- महिलाएं देशभर में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं: २ * ७ जिलों में महिलाएं कार्यबल का कम से कम एक-तिहाई हिस्सा हैं, जो असंगठित उद्यमों में महिलाओं की महत्वपूर्ण भागीदारी को दर्शाता है।

3. प्रधानमंत्री ने आचार्य विनोबा भावे की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आचार्य विनोबा भावे की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और सामाजिक सुधार, अहिंसा तथा समाज के उत्थान में उनके स्थायी योगदान को स्मरण किया। उन्होंने विनोबा भावे के प्रेरणादायक सार्वभौमिक आह्वान, "जय जगत", पर प्रकाश डाला, जिसने मानवता को सर्वोपरि रखा और वैश्विक सद्भाव तथा कल्याण के उनके दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित किया। प्रधानमंत्री ने गांधीवादी सिद्धांतों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और सामाजिक न्याय, समानता तथा शांतिपूर्ण परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए भूदान आंदोलन के माध्यम से किए गए उनके प्रयासों को भी स्मरण किया।



2. NSO Releases First-Ever District-Level Estimates for India's Unincorporated Non-Agricultural Sector

The National Statistical Office has released India's first-ever district-level estimates for the unincorporated non-agricultural sector, offering granular insights into economic activity across districts. The estimates reveal significant geographical concentration, with the top 50 districts accounting for nearly 33 percent of total sector activity. The data provides detailed information on enterprises, employment and economic output, helping policymakers better understand regional variations. It is expected to strengthen evidence-based policymaking and support more targeted planning for the country's large unincorporated business sector.



Key Points:

- District-level data improves policymaking: NSO has released district-level estimates for India's unincorporated non-agricultural sector for the first time using ASUSE 2025 data.
- Top districts drive major activity: The top 50 districts account for nearly one-third of establishments, workforce and Gross Value Added generated by the sector.
- Women contribute significantly nationwide: In 237 districts, women constitute at least one-third of the workforce, highlighting substantial female participation in unincorporated enterprises.

3. Prime Minister Commemorates Acharya Vinoba Bhave on His Birth Anniversary

Prime Minister Narendra Modi paid tribute to Acharya Vinoba Bhave on his birth anniversary, recalling his enduring contributions to social reform, non-violence and the upliftment of society. He highlighted Vinoba Bhave's stirring universal call, "Jai Jagat", which placed humanity above all and reflected his vision of global harmony and welfare. The Prime Minister also remembered his commitment to Gandhian principles and his efforts through the Bhoodan movement to promote social justice, equality and peaceful transformation.



मुख्य बिंदु:

- गांधीवादी आदर्श निरंतर प्रेरित करते हैं: आचार्य विनोबा भावे को गांधीवादी सिद्धांतों, सामाजिक सुधार और वंचित समुदायों के सशक्तीकरण के लिए शांतिपूर्ण प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए स्मरण किया जाता है।
- सामाजिक सशक्तीकरण केंद्र में रहा: वंचित वर्गों के उत्थान तथा निःस्वार्थता, एकता और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने के प्रति उनकी आजीवन प्रतिबद्धता पीढ़ियों को प्रेरित करती रही है।
- विरासत राष्ट्रीय विकास का मार्गदर्शन करती है: उनके विचार और आदर्श समावेशी, सशक्त और विकसित भारत के निर्माण की दृष्टि के लिए आज भी प्रासंगिक हैं।

4. प्रधानमंत्री ने ९/११ की बरसी पर आतंकवाद से निपटने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद से मुकाबला करने के लिए भारत की अटूट प्रतिबद्धता दोहराई और संयुक्त राज्य अमेरिका में ११ सितंबर २००१ को हुए आतंकवादी हमलों से प्रभावित सभी लोगों के प्रति एकजुटता व्यक्त की। हमलों की बरसी पर उन्होंने पीड़ितों को स्मरण किया और सभी प्रकार के आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक एकता की आवश्यकता पर जोर दिया। संदेश में शांति, सुरक्षा और आतंकवाद के खतरे से मुक्त विश्व को बढ़ावा देने के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर काम करने के भारत के निरंतर संकल्प को रेखांकित किया गया।



मुख्य बिंदु:

- आतंकवाद के लिए वैश्विक सहयोग आवश्यक है: भारत ने दोहराया कि आतंकवाद एक वैश्विक चुनौती बना हुआ है, जिसके लिए सामूहिक अंतरराष्ट्रीय कार्रवाई, मजबूत सहयोग और आतंकवादी नेटवर्क के खिलाफ दृढ़ कदम उठाने की आवश्यकता है।
- पीड़ित स्मरण के केंद्र में रहते हैं: बरसी विनाशकारी ९/११ हमलों की याद दिलाती है और सभी रूपों के आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता की आवश्यकता को मजबूत करती है।
- भारत निर्णायक कार्रवाई पर जोर देता है: भारत आतंकवादी संगठनों, उनके समर्थकों, वित्तपोषण नेटवर्क और सुरक्षित पनाहगाह उपलब्ध कराने वालों के खिलाफ समन्वित अंतरराष्ट्रीय प्रयासों की निरंतर वकालत करता है।

Key Points:

- Gandhian ideals continue inspiring: Acharya Vinoba Bhave is remembered for promoting Gandhian principles, social reform and peaceful efforts for empowering marginalised communities.
- Social empowerment remained central: His lifelong commitment to uplifting disadvantaged sections and promoting selflessness, unity and social harmony continues to inspire generations.
- Legacy guides national development: His thoughts and ideals remain relevant to the vision of building an inclusive, empowered and developed India.

4. Prime Minister Reaffirms India's Commitment to Countering Terrorism on 9/11 Anniversary

- Prime Minister Narendra Modi reaffirmed India's unwavering commitment to combating terrorism and expressed solidarity with all those affected by the September 11, 2001 terrorist attacks in the United States. On the anniversary of the attacks, he remembered the victims and emphasized the need for global unity against terrorism in all its forms. The message highlighted India's continued resolve to work with the international community to promote peace, security and a world free from the threat of terrorism.



Key Points:

- Terrorism demands global cooperation: India reiterated that terrorism remains a global challenge requiring collective international action, stronger cooperation and firm measures against terrorist networks.
- Victims remain central to remembrance: The anniversary recalls the devastating 9/11 attacks and reinforces the need for solidarity against terrorism in all forms.
- India stresses decisive action: India continues advocating coordinated international efforts against terrorist organisations, their supporters, financing networks and those providing safe havens.

5. बैंकों की पुस्तकों का साक्ष्य अधिनियम, २०२६ १ अक्टूबर से लागू होने वाला है

बैंकों की पुस्तकों का साक्ष्य अधिनियम, २०२६ १ अक्टूबर से लागू होने वाला है, जिसमें बैंकिंग अभिलेखों को प्रस्तुत करने और न्यायालय में बैंक अधिकारियों की उपस्थिति को नियंत्रित करने वाले अद्यतन प्रावधान शामिल हैं। नए ढांचे के तहत, जब बैंक अधिकारियों को गैर-पक्षकार के रूप में बुलाया जाता है, तो न्यायाधीश को उनकी उपस्थिति आवश्यक होने के लिए लिखित रूप में "विशेष कारण" दर्ज करना होगा। इस प्रावधान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंक अधिकारियों को केवल आवश्यकता होने पर ही न्यायालय में बुलाया जाए, जिससे बैंकिंग परिचालन में अनावश्यक व्यवधान कम हों और न्यायिक कार्यवाही को भी समर्थन मिले।



मुख्य बिंदु:

- नया कानून बैंकिंग साक्ष्य को आधुनिक बनाता है: यह अधिनियम भौतिक, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल, आभासी और क्लाउड-आधारित अभिलेखों को मान्यता देकर समकालीन बैंकिंग के लिए साक्ष्य संबंधी नियमों को अद्यतन करता है।
- डिजिटल अभिलेखों को कानूनी मान्यता मिलती है: इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल बैंकर अभिलेख निर्धारित प्रमाणन, प्रमाणीकरण, अखंडता और सुरक्षा आवश्यकताओं के अधीन साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए जा सकते हैं।
- कार्यान्वयन १ अक्टूबर से शुरू: केंद्र सरकार ने अधिनियम के सभी प्रावधानों के प्रारंभ होने की तारीख १ अक्टूबर २०२६ अधिसूचित की है।

6. भारत ने महत्वपूर्ण खनिजों को ऊर्जा सुरक्षा, औद्योगिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक बताया

लिथियम, कोबाल्ट और दुर्लभ मृदा तत्व जैसे महत्वपूर्ण खनिज भारत की ऊर्जा सुरक्षा, औद्योगिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक हैं तथा स्वच्छ ऊर्जा, उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स, परिवहन और रक्षा अनुप्रयोगों को समर्थन देते हैं। *६,००० करोड़ रुपये की योजना से समर्थित राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन का उद्देश्य घरेलू और अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करना तथा आयात पर निर्भरता से उत्पन्न कमजोरियों को कम करना है। इन खनिजों के अधिक अन्वेषण, प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण से औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता, तकनीकी स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता के व्यापक लक्ष्य को बढ़ावा मिल सकता है।



Bankers' Books Evidence Act, 2026 Set to Take Effect from October 1

The Bankers' Books Evidence Act, 2026 is set to come into effect from October 1, introducing updated provisions governing the production of banking records and the appearance of bank officials in court. Under the new framework, when bank officials are summoned as non-parties, the judge must record a "special cause" in writing for requiring their presence. The provision seeks to ensure that bank officials are called to court only when necessary, reducing avoidable disruptions to banking operations while supporting judicial proceedings.



Key Points:

- New law modernises banking evidence: The Act updates evidentiary rules for contemporary banking by recognising physical, electronic, digital, virtual and cloud-based records.
- Digital records gain legal recognition: Electronic and digital bankers' records can be presented as evidence subject to prescribed certification, authentication, integrity and security requirements.
- Implementation begins October first: The Central Government has notified October 1, 2026 as the commencement date for all provisions of the Act.

6. India Highlights Critical Minerals as Vital for Energy Security, Industrial Growth and National Security

Critical minerals such as lithium, cobalt and rare earth elements are vital for India's energy security, industrial growth and national security, supporting clean energy, advanced electronics, transport and defence applications. The National Critical Mineral Mission, backed by a 36,000 crore rupee scheme, aims to strengthen domestic and international supply chains and reduce vulnerabilities from import dependence. Greater exploration, processing and recycling of these minerals can enhance industrial competitiveness, technological independence and India's broader goal of self-reliance.



मुख्य बिंदु:

- महत्वपूर्ण खनिज रणनीतिक क्षेत्रों को समर्थन देते हैं: लिथियम, कोबाल्ट और दुर्लभ मृदा तत्व जैसे खनिज स्वच्छ ऊर्जा, उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स, परिवहन और रक्षा के लिए आवश्यक हैं।
- मिशन घरेलू आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करता है: राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन का उद्देश्य आयात पर निर्भरता से उत्पन्न कमजोरियों को कम करते हुए घरेलू और अंतरराष्ट्रीय खनिज आपूर्ति को सुरक्षित करना है।
- अन्वेषण तकनीकी स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है: महत्वपूर्ण खनिजों के अधिक अन्वेषण, प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण से औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता, ऊर्जा सुरक्षा और तकनीकी आत्मनिर्भरता को मजबूत किया जा सकता है।

7. ब्रिक्स भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी ने नई दिल्ली में नवाचार और उद्यमिता को प्रदर्शित किया

- ब्रिक्स भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी ११ और १२ सितंबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित की जा रही है, जिसमें भारत के डीप-टेक नवाचार और उद्यमशील क्षमताओं को प्रदर्शित किया जा रहा है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा समन्वित इस प्रदर्शनी में व्यापक भारत इनोवेट्स समूह से चयनित *७ भारतीय डीप-टेक स्टार्टअप और उद्यम शामिल हैं। यह आयोजन व्यावसायिक संपर्क, प्रौद्योगिकी साझेदारी, निवेश के अवसरों और अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंच के लिए एक मंच प्रदान करता है, साथ ही ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान भारत की प्राथमिकताओं का समर्थन करता है और नवाचार के क्षेत्र में वैश्विक सहयोग को मजबूत करता है।



मुख्य बिंदु:

- डीप-टेक स्टार्टअप नवाचार प्रदर्शित करते हैं: प्रदर्शनी में व्यापक भारत इनोवेट्स समूह से चयनित *७ भारतीय डीप-टेक स्टार्टअप और उद्यम शामिल हैं, जिन्हें पहले नीस में प्रदर्शित किया गया था।
- अंतरराष्ट्रीय साझेदारियों पर ध्यान: यह आयोजन भारतीय नवप्रवर्तकों के लिए व्यवसाय-से-व्यवसाय संपर्क, प्रौद्योगिकी साझेदारी, निवेश संबंधी चर्चाओं और अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंच के अवसर प्रदान करता है।

Key Points:

- Critical minerals support strategic sectors: Minerals such as lithium, cobalt and rare earth elements are essential for clean energy, advanced electronics, transport and defence.
- Mission strengthens domestic supply chains: The National Critical Mineral Mission aims to secure domestic and international mineral supplies while reducing vulnerabilities arising from import dependence.
- Exploration drives technological independence: Greater exploration, processing and recycling of critical minerals can strengthen industrial competitiveness, energy security and technological self-reliance.

7. BRICS Bharat Innovates Exposition Showcases Innovation and Entrepreneurship in New Delhi

- The BRICS Bharat Innovates Exposition is being held at Bharat Mandapam in New Delhi on September 11 and 12, showcasing India's deep-tech innovation and entrepreneurial capabilities. Coordinated by the Ministry of Education, the exposition features 37 Indian deep-tech startups and ventures selected from the broader Bharat Innovates cohort. The event provides a platform for business engagements, technology partnerships, investment opportunities and international market access, while supporting India's priorities during its BRICS Chairship and strengthening global collaboration in innovation.



Key Points:

- Deep-tech startups showcase innovation: The exposition features 37 Indian deep-tech startups and ventures selected from the larger Bharat Innovates cohort showcased earlier in Nice.
- International partnerships receive focus: The event creates opportunities for business-to-business engagements, technology partnerships, investment discussions and international market access for Indian innovators.

- प्रदर्शनी ब्रिक्स के अनुरूप: ११ और १२ सितंबर को भारत मंडपम में आयोजित यह आयोजन भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के केंद्रित विषयों का समर्थन करता है।

8. राष्ट्रीय सम्मेलन ने जैवसमकक्षों के लिए गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया

“जैवसमकक्षों की गुणवत्ता और सुरक्षा” पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन बेंगलुरु में आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य “भारत के जैव-



औषधि शक्ति दृष्टिकोण को सुदृढ़ करना” की व्यापक दृष्टि के तहत भारत के जैवसमकक्ष पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है। सम्मेलन में विनिर्माण, अनुसंधान, विनियमन, शिक्षा जगत और औषधि-सुरक्षा निगरानी के विशेषज्ञों को एक साथ लाया गया, जिन्होंने गुणवत्ता, सुरक्षा, नियामक विज्ञान और विनिर्माण प्रथाओं पर चर्चा की। इस पहल का उद्देश्य नियामक नवाचार, उच्च-गुणवत्ता वाले जैवसमकक्ष विकास और मजबूत उद्योग सहयोग को बढ़ावा देना है, जिससे भारत को एक प्रमुख वैश्विक जैव-औषधीय केंद्र के रूप में उभरने की महत्वाकांक्षा को समर्थन मिले।

मुख्य बिंदु:

- जैवसमकक्ष मानकों पर ध्यान: सम्मेलन भारत में जैवसमकक्षों के लिए गुणवत्ता, सुरक्षा, नियामक विज्ञान, विनिर्माण और औषधि-सुरक्षा निगरानी प्रथाओं में सुधार पर केंद्रित है।
- उद्योग सहयोग नवाचार को समर्थन देता है: भारत के जैव-औषधीय पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए विनिर्माण, अनुसंधान, विनियमन, शिक्षा जगत और औषधि-सुरक्षा निगरानी के विशेषज्ञों को एक साथ लाया गया है।
- जैव-औषधि दृष्टिकोण को गति: चर्चाएं नियामक नवाचार और उच्च-गुणवत्ता वाले जैवसमकक्ष विकास के माध्यम से भारत को एक मजबूत वैश्विक जैव-औषधीय केंद्र बनाने की महत्वाकांक्षा का समर्थन करती हैं।

- Exposition aligns with BRICS: Held at Bharat Mandapam on September 11 and 12, the event supports India's BRICS Chairship focus.

8. National Conference Focuses on Enhancing Quality and Safety Standards for Biosimilars

A two-day National Conference on “Quality and Safety of Biosimilars” was organized in Bengaluru to strengthen



India's biosimilar ecosystem under the broader vision of “Strengthening India's Biopharma SHAKTI Vision”. The conference brought together experts from manufacturing, research, regulation, academia and pharmacovigilance to discuss quality, safety, regulatory science and manufacturing practices. The initiative aims to promote regulatory innovation, high-quality biosimilar development and stronger industry collaboration, supporting India's ambition to emerge as a leading global biopharmaceutical hub.

Key Points:

- Biosimilar standards receive attention: The conference focuses on improving quality, safety, regulatory science, manufacturing and pharmacovigilance practices for biosimilars in India.
- Industry collaboration supports innovation: Experts from manufacturing, research, regulation, academia and pharmacovigilance are brought together to strengthen India's biopharmaceutical ecosystem.
- Biopharma vision gains momentum: Discussions support India's ambition to become a stronger global biopharmaceutical hub through regulatory innovation and high-quality biosimilar development.

9. भारत ने ब्रिक्स देशों के बीच अधिक संतुलित और लचीले व्यापार का आह्वान किया

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स व्यापार मंच पर ब्रिक्स देशों के बीच अधिक संतुलित और लचीले व्यापार का आह्वान किया तथा विविधतापूर्ण और विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखलाओं की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने व्यक्तिगत बाजारों पर अत्यधिक निर्भरता से उत्पन्न कमजोरियों को कम करने के लिए कच्चे खनिजों सहित उत्पादों के लिए बाजार खुले रखने पर जोर दिया। ब्रिक्स सदस्यों के बीच अधिक सहयोग निवेश, प्रौद्योगिकी साझेदारी और बाजार तक पहुंच को बढ़ावा दे सकता है तथा वाणिज्यिक संबंधों को मजबूत कर सकता है। इस दृष्टिकोण का उद्देश्य साझा विकास को समर्थन देना और अधिक लचीली वैश्विक व्यापार प्रणाली का निर्माण करना है।



India Calls for More Balanced and Resilient Trade Among BRICS Nations

Union Minister Piyush Goyal called for more balanced and resilient trade among BRICS nations at the BRICS Business Forum, stressing the need for diversified and reliable supply chains. He emphasized keeping markets open for products, including raw minerals, to reduce vulnerabilities arising from excessive dependence on individual markets. Greater cooperation among BRICS members can promote investment, technology partnerships and market access while strengthening commercial linkages. The approach aims to support shared growth and create a more resilient global trading system.



मुख्य बिंदु:

- संतुलित व्यापार साझा विकास को समर्थन देता है: भारत ने ब्रिक्स सदस्यों के बीच अधिक संतुलित और लचीले व्यापार की वकालत की तथा विकासशील और उभरती अर्थव्यवस्थाओं को लाभ पहुंचाने वाले सहयोग पर जोर दिया।
- आपूर्ति श्रृंखलाओं में अधिक लचीलेपन की आवश्यकता: ब्रिक्स देशों को विविधतापूर्ण आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने और व्यक्तिगत बाजारों पर अत्यधिक निर्भरता के कारण उत्पन्न कमजोरियों को कम करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।
- सहयोग व्यापार के अवसरों का विस्तार कर सकता है: सदस्यों के बीच अधिक आर्थिक समन्वय निवेश, प्रौद्योगिकी साझेदारी, बाजार तक पहुंच और मजबूत वाणिज्यिक संबंधों को सुगम बना सकता है।

Key Points:

- Balanced trade supports shared growth: India advocated more balanced and resilient trade among BRICS members while emphasising cooperation that benefits developing and emerging economies.
- Supply chains need greater resilience: BRICS countries were encouraged to strengthen diversified supply chains and reduce vulnerabilities caused by excessive dependence on individual markets.
- Cooperation can expand trade opportunities: Greater economic coordination among members can facilitate investment, technology partnerships, market access and stronger commercial linkages.

10. वरिष्ठ ग्रामीण विकास अधिकारियों ने मणिपुर में कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा की

ग्रामीण विकास मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने ग्रामीण विकास और कल्याणकारी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए मणिपुर के बिष्णुपुर और



चुराचांदपुर जिलों में दो दिवसीय “क्षेत्र अधिकारी” समीक्षा दौरा किया। समीक्षा में चल रही परियोजनाओं की प्रगति, लाभों का समय पर वितरण और विभागों के बीच समन्वय पर ध्यान केंद्रित किया गया। अधिकारियों ने विकास गतिविधियों में देरी करने वाली चुनौतियों का समाधान करते हुए पारदर्शिता, जवाबदेही और जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन को मजबूत करने पर जोर दिया। इस अभ्यास का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि पात्र लाभार्थियों को सरकारी सहायता प्रभावी और कुशल तरीके से प्राप्त हो।

मुख्य बिंदु:

- योजना कार्यान्वयन की समीक्षा की गई: वरिष्ठ अधिकारियों ने मणिपुर में ग्रामीण विकास और कल्याणकारी कार्यक्रमों की प्रगति का आकलन किया, जिसमें प्रभावी कार्यान्वयन और लाभों के समय पर वितरण पर ध्यान दिया गया।
- विकास परियोजनाओं की करीबी निगरानी: अधिकारियों ने चल रही पहलों की समीक्षा की और कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियों का समाधान करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में विकास गतिविधियों में तेजी लाने के लिए विभागों के बीच समन्वय पर जोर दिया।
- कल्याणकारी योजनाओं का वितरण प्राथमिकता बना रहा: समीक्षा में यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया कि पात्र लाभार्थियों को सरकारी सहायता मिले तथा ग्रामीण विकास योजनाओं के कार्यान्वयन में पारदर्शिता, जवाबदेही और जमीनी स्तर के कार्यान्वयन को मजबूत किया जाए।

— ★ ★ ★ —

10. Senior Rural Development Officials Review Implementation of Welfare Schemes in Manipur

Senior officers from the Ministry of Rural Development conducted a two-day “Area Officer” review visit across Bishnupur and



Churachandpur districts of Manipur to assess the implementation of rural development and welfare programmes. The review focused on the progress of ongoing projects, timely delivery of benefits and coordination among departments. Officials emphasized strengthening transparency, accountability and grassroots-level implementation while addressing challenges that could delay development activities. The exercise aimed to ensure eligible beneficiaries receive government assistance effectively and efficiently.

Key Points:

- Scheme implementation receives review: Senior officials assessed the progress of rural development and welfare programmes in Manipur, focusing on effective implementation and timely delivery of benefits.
- Development projects face closer monitoring: Officials reviewed ongoing initiatives and stressed coordination among departments to address implementation challenges and accelerate development activities across rural areas.
- Welfare delivery remains priority: The review emphasised ensuring eligible beneficiaries receive government assistance while strengthening transparency, accountability and grassroots-level implementation of rural development schemes.

— ★ ★ ★ —

दैनिक समसामयिक

DAILY

CURRENT AFFAIRS



MCQs

प्रश्नोत्तरी

Q1. सितंबर २०२६ में, ग्रामीण विकास मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने मणिपुर के किन दो जिलों में दो दिवसीय “क्षेत्र अधिकारी” समीक्षा दौरा किया?

- (a) इम्फाल पश्चिम और थौबल
- (b) तामेंगलॉन्ग और जिरिबाम
- (c) उखरुल और सेनापति
- (d) बिष्णुपुर और चुराचांदपुर

Q2. सितंबर २०२६ में ब्रिक्स व्यापार मंच पर बोलते हुए, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुनिश्चित करने के लिए किस उपाय पर जोर दिया?

- (a) कच्चे खनिजों सहित उत्पादों के लिए बाजार खुले रखना
- (b) सदस्य देशों में प्रतिबंधात्मक आयात शुल्क
- (c) सभी सेवा क्षेत्रों के संबंध में सार्वभौमिक प्रतिबंध
- (d) संप्रभु संस्थाओं के लिए विशेष निर्यात गलियारे

Q3. सितंबर २०२६ में “जैवसमकक्षों की गुणवत्ता और सुरक्षा” पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन बेंगलुरु में किस व्यापक राष्ट्रीय दृष्टिकोण विषय के तहत आयोजित किया गया?

- (a) भारत की सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा मिशन योजना
- (b) विकसित भारत चिकित्सा प्रौद्योगिकी मिशन
- (c) व्यापक राष्ट्रीय औषधि दृष्टिकोण २० * ०
- (d) भारत के जैव-औषधि शक्ति दृष्टिकोण को सुदृढ़ करना

Q4. सितंबर २०२६ में डीप-टेक स्टार्टअप को प्रदर्शित करने के लिए आयोजित “ब्रिक्स भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी” का समन्वय किस केंद्रीय मंत्रालय ने किया?

- (a) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
- (b) शिक्षा मंत्रालय
- (c) कौशल विकास मंत्रालय
- (d) नीति आयोग

Q5. सितंबर २०२६ में महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करने के लिए *६,००० करोड़ रुपये की योजना से समर्थित किस सरकारी पहल को रेखांकित किया गया?

- (a) राष्ट्रीय हरित ऊर्जा गलियारा
- (b) सौर पीवी के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना
- (c) राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन
- (d) भारत खनिज अन्वेषण योजना

Q1. In September 2026, senior officers from the Ministry of Rural Development conducted a two-day 'Area Officer' review visit across which two districts of Manipur?

- (a) Imphal West and Thoubal
- (b) Tamenglong and Jiribam
- (c) Ukhrul and Senapati
- (d) Bishnupur and Churachandpur

Q2. Speaking at the BRICS Business Forum in September 2026, Union Minister Piyush Goyal emphasized which measure to ensure resilient supply chains?

- (a) Open markets for products including raw minerals
- (b) Restrictive import tariffs across member nations
- (c) Universal bans regarding all service sectors
- (d) Exclusive export corridors for sovereign entities

Q3. In September 2026, the two-day National Conference on 'Quality and Safety of Biosimilars' was organized in Bengaluru under which overarching national vision theme?

- (a) India's Universal Healthcare Mission Plan
- (b) Viksit Bharat MedTech Mission
- (c) Comprehensive National Pharma Vision 2030
- (d) Strengthening India's Biopharma SHAKTI Vision

Q4. Which Union Ministry coordinated the 'BRICS Bharat Innovates Exposition' held in September 2026 to highlight deep-tech startups?

- (a) Ministry of Commerce and Industry
- (b) Ministry of Education
- (c) Ministry of Skill Development
- (d) NITI Aayog

Q5. Which government initiative backed by a 36,000 crore rupee scheme was highlighted in September 2026 to secure critical mineral supply chains?

- (a) National Green Energy Corridor
- (b) Production Linked Incentive for Solar PV
- (c) National Critical Mineral Mission
- (d) Bharat Mineral Exploration Scheme

Q6. १ अक्टूबर २०२६ से प्रभावी होने वाले प्रावधानों के तहत, गैर-पक्षकार के रूप में न्यायालय में बुलाए गए बैंक अधिकारियों के लिए न्यायाधीश से कौन-सा विशिष्ट आदेश आवश्यक है?

- (a) भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर से लिखित अनुमति
- (b) कोई न्यायालय बैंक अधिकारियों को नहीं बुला सकता
- (c) वित्त मंत्रालय से स्वीकृति
- (d) लिखित रूप में "विशेष कारण" दर्ज करना

Q7. ११ सितंबर २०२६ को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस प्रमुख वैश्विक घटना की बरसी पर वैश्विक एकजुटता का संदेश जारी किया और आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई?

- (a) मुंबई २६/११ हमले
- (b) अमेरिका में ९/११ के आतंकवादी हमले
- (c) पुलवामा हमला
- (d) क्राइस्टचर्च हमले

Q8. सितंबर २०२६ में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आचार्य विनोबा भावे की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए विशेष रूप से उनके किस प्रेरणादायक सार्वभौमिक आह्वान को रेखांकित किया, जिसने मानवता को सर्वोपरि रखा?

- (a) जय जवान जय किसान
- (b) जय जगत
- (c) गरीबी हटाओ
- (d) इंकलाब जिंदाबाद

Q9. सितंबर २०२६ में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी पहली बार के जिला-स्तरीय अनुमानों के अनुसार, शीर्ष ५० जिलों द्वारा कुल क्षेत्रीय गतिविधि का कितना प्रतिशत संचालित किया जाता है?

- (a) लगभग २० प्रतिशत
- (b) लगभग २० प्रतिशत
- (c) लगभग १० प्रतिशत
- (d) लगभग ५० प्रतिशत

Q10. सितंबर २०२६ में, भारत के उपराष्ट्रपति ने समृद्ध सांस्कृतिक विविधता और समावेशी विकास मॉडल के कारण निम्नलिखित में से किस केंद्रशासित प्रदेश को "लघु भारत" कहा?

- (a) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
- (b) लक्षद्वीप
- (c) दमन और दीव
- (d) जम्मू और कश्मीर

Q6. Under the provisions taking effect from October 1, 2026, bank officials summoned to court as non-parties require which specific mandate from the judge?

- (a) Written permission from the Governor of RBI
- (b) No court can summon bank officials
- (c) Clearance from the Ministry of Finance
- (d) Recording of a 'special cause' in writing

Q7. On September 11, 2026, Prime Minister Narendra Modi issued a message of global solidarity and reaffirmed India's commitment to counter terrorism on the anniversary of which major global event?

- (a) Mumbai 26/11 Attacks
- (b) US 9/11 Terror Attacks
- (c) Pulwama Attack
- (d) Christchurch Attacks

Q8. In September 2026, Prime Minister Narendra Modi paid tribute to Acharya Vinoba Bhave on his birth anniversary, specifically highlighting which stirring universal call given by him that placed humanity above all?

- (a) Jai Jawan Jai Kisan
- (b) Jai Jagat
- (c) Garibi Hatao
- (d) Inquilab Zindabad

Q9. According to the first-ever district-level estimates released by the National Statistical Office (NSO) in September 2026, what percentage of total sector activity is driven by the top 50 districts?

- (a) Nearly 33 percent
- (b) Nearly 20 percent
- (c) Nearly 10 percent
- (d) Nearly 50 percent

Q10. In September 2026, the Vice President of India referred to which of the following Union Territories as 'Mini India' due to its rich cultural diversity and inclusive growth model?

- (a) Andaman and Nicobar Islands
- (b) Lakshadweep
- (c) Daman and Diu
- (d) Jammu and Kashmir

उत्तरमाला (Answer Key)

1 D 2 A 3 D 4 B 5 C 6 D 7 B 8 B 9 A 10 C

